

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-275
उत्तर दिनांक 11.03.2026 को दिया गया

दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाना

*275. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश
श्री इटेला राजेंदर

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने खनिज समृद्ध राज्यों में समर्पित गलियारों के माध्यम से दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के संबंध में केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं का संज्ञान लिया है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे मानदंडों और आधार का ब्यौरा क्या है जिनके तहत इस पहल के अंतर्गत सहायता हेतु ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को चिह्नित किया गया है तथा इस संबंध में उठाए गए कदमों, स्वीकृत और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस कार्यनीति को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकारों के साथ किए गए परामर्श सहित किसी भी अंतर-सरकारी परामर्श का ब्यौरा क्या है;
- (घ) घरेलू दुर्लभ मृदा संसाधन क्षमता और प्रसंस्करण तत्परता के संबंध में तैयार की गई किसी भी रिपोर्ट या किए गए मूल्यांकन की स्थिति क्या है; और
- (ङ) इन पहलों के अंतर्गत दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा और मापनीय महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं तथा देश में ऐसी योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

“दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाना” के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश व श्री इटेला राजेंद्र द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 275 के भाग (क) से (ड), जिसका उत्तर दिनांक 11.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

(क), (ख) व (ग) हां। केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध तटीय राज्यों में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित विरल मृदा गलियारे (कॉरिडोर) स्थापित करने हेतु समर्थन देने की घोषणा की गई। इन दुर्लभ मृदा गलियारों का उद्देश्य NdPr (नियोडिमियम-प्रसेओडिमियम) और समेरियम ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाकर तथा आरई चुम्बकों के उत्पादन की घरेलू मांग को बढ़ावा देकर भारत में एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दुर्लभ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है और साथ ही टाइटेनियम और जिर्कोनियम आदि की मूल्य श्रृंखला में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। घोषणा के बाद, राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से आरई गलियारों की स्थापना संबंधी व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत या व्यय नहीं की गई है।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) की एक संघटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में तटीय / अंतर्देशीय / नदी तटीय प्लेसर बालू (समुद्र तटीय बालू खनिजों में) और कठोर शैल क्षेत्रों में आरईई संसाधनों का आकलन किया है।

एएमडी द्वारा अनुमानित आरईई संसाधनों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में समुद्र तटीय और टेरी / लाल बालू क्षेत्रों में और झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ भागों में अंतर्देशीय जलोढ़ क्षेत्रों में पाए जाने वाले 13.15 मिलियन टन मोनाज़ाइट संसाधन जिसमें लगभग 7.23 मिलियन टन समतुल्य दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ) है।
- अंबाडुंगर क्षेत्र, छोटा उदेपुर जिला, गुजरात और भाटीखेड़ा और दंतला क्षेत्र, बालोतरा (पूर्ववर्ती बाड़मेर) जिला, राजस्थान के कठोर शैल इलाकों में 1.29 मिलियन टन *स्वस्थाने* आरईओ।

(ड) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकीकृत दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) विनिर्माण को बढ़ाने के लिए दिनांक 26 नवंबर, 2025 को 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सिल्वरित दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। योजना की कुल अवधि, एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए 2 वर्ष की अवधि और आरईपीएम की बिक्री पर प्रोत्साहन वितरण के लिए 5 वर्ष सहित योजना मंजूरी की तारीख से 7 वर्ष होगी। आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड ने ऐसी योजना, जिसके लिए खनन और प्रसंस्करण क्षमताएं मौजूद हैं, के तहत चुंबक निर्माण के लिए चयनित बोलीकर्ताओं को 500 टीपीए NdPr ऑक्साइड की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।